

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2, 3 और 4 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसने घरेलू और वैश्विक दोनों के वर्तमान समष्टि आर्थिक और वित्तीय विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्नत संभावनाओं की समीक्षा की। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ने के लिए मतदान किया। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक आवश्यक हो तब तक मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को जारी रखा जाए - कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जाए तथा COVID-19 के प्रभाव को कम किया जाए। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है। रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।

मैं आज इस अवसर पर अपनी मौद्रिक नीति के निर्णय में योगदान देने वाली बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए समिति के सदस्यों की सराहना करना चाहता हूँ। मैं रिजर्व बैंक में हमारी टीमों को उनके विश्लेषणात्मक और बौद्धिक सहायता, तथा तार्किक सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

मैं आज अपनी बात एमपीसी के निर्णय और उसके औचित्य के दौरान आए विचारों को स्थापित करते हुए शुरू करना चाहता हूँ। एमपीसी का विचार था कि सर्दियों के महीनों में नष्ट होने योग्य वस्तुओं की कीमतों में राहत और बम्पर खरीफ के आगमन के साथ मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी की संभावना है। यह संवृद्धि के समर्थन में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्थान का उपयोग करने से वर्तमान समय में मौद्रिक नीति को बाधित करता है। उसी समय, बहाली के संकेत वैविध्यपूर्ण होने से बहुत दूर हैं और निरंतर नीतिगत समर्थन पर निर्भर हैं। आपूर्ति श्रृंखला अवरोधों,

अत्यधिक मार्जिन और अप्रत्यक्ष करों द्वारा संवर्धित किए जा रहे मुद्रास्फीति सीढ़ी को तोड़ने के लिए अग्रसक्रिय आपूर्ति प्रबंधन कार्यनीतियों के लिए एक छोटी विंडो उपलब्ध है। आपूर्ति पक्ष द्वारा संचालित मुद्रास्फीति के दबावों को कम करने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। एमपीसी व्यापक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संभालने के लिए मूल्य स्थिरता के सभी खतरों की बारीकी से निगरानी करेगा। तदनुसार, एमपीसी ने आज निर्णय लिया कि नीतिगत दर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए और जब तक आवश्यक हो, तब तक निभावकारी रुख जारी रखा जाए- कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान - ताकि यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जाए तथा COVID-19 के प्रभाव को कम किया जाए।

वर्ष 2020 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इसने हमारी क्षमताओं और यहां तक कि शक्ति, धैर्य और भाग्य के हमारे आंतरिक भंडार का परीक्षण और विस्तार किया है। जैसे-जैसे वर्ष की समाप्ति करीब आ रही है, वैसे ही हमारे कार्यों और परिणामों की समीक्षा करना उचित होगा कि कैसे हमने महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेरे विचार में, इस सर्वव्यापी प्रयास में, हर उस ट्राइल को लड़ने और उस पर काबू पाने का हमारा दृढ़ संकल्प था, जो हमारी सहायता के लिए तैयार था। मुझे यहां महात्मा गांधी के शब्द याद आ रहे हैं और उसे मैं उद्धृत करता हूँ: “शक्ति एक अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।” वहां से सबक लेते हुए, मैं आगे के लिए हमारे विजन को स्थापित करने की कोशिश करूँगा।

2020: एक यादगार वर्ष

जब इस महामारी के निश्चित इतिहास को लिखा जाएगा, तो वर्ष 2020 को आधुनिक सभ्यता के इतिहास में एक निर्दिष्ट वर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसे महामारी द्वारा चिह्नित किया जाएगा, जो कि 1918 के स्पैनिश फ्लू के अपने पैमाने से तुलनीय और 1930 के दशक के महामंदी के आर्थिक नुकसान से अधिक है। COVID-19 तब ही आया जब दुनिया गतिविधि के एक समकालिक मंदी की चपेट में थी जिसने इस यातना को और भी कष्टदायी बना दिया। इस मानवीय और आर्थिक त्रासदी के साथ-साथ, इतिहास केंद्रीय बैंकों और सरकारों, स्वास्थ्य प्रणालियों

* गवर्नर का वक्तव्य - 4 दिसंबर 2020

और कर्मियों, नागरिक समाज संगठनों और सबसे ऊपर, आम लोगों की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया को भी दर्ज करेगा।

साथ में, हम मानवीय नुकसानों को नियंत्रित करने में कामयाब रहे, यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय प्रणाली और बाजार सामान्य रूप से काम करते रहे, वित्त उपलब्ध रहे और प्रवाहमान रहे, और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इसका परिणाम यह हुआ कि निकट अवधि के वित्तीय स्थिरता जोखिमों को समाहित कर लिया गया है। आर्थिक संकुचन सहज होने लगे हैं, उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह में सुधार हुआ है और मजबूत क्रेडिट रेटिंग वाले लोगों के लिए हार्ड मुद्रा बांड का निर्गम संवर्धित हुआ है।

इस पूरी अवधि में, रिज़र्व बैंक ने वायरस द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक रूप से कार्य किया। सम्पूर्ण प्रयास यह है कि आगे बढ़ते हुए, उत्पादन और रोजगार के नुकसान को समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के वातावरण में जल्दी से पुनः प्राप्त किया जाए।

हमारे कार्यसूची में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण के साथ, हम तेजी से दो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति को हल कर सकते हैं। हम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं और इस मोर्चे पर जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। जबकि हम लगातार विनियमों को मजबूत करने और अपनी निगरानी को गहन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बैंकों और एनबीएफसी जैसी वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को भी अभिशासन की गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। वे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता से संबंधित मामलों में रक्षा की पहली पंक्ति हैं।

ऋण प्रबंधक और सरकार को बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का 2020 में पूर्णतया परीक्षण किया गया था, जिसे बाजार में उधार के उच्चतम स्तर द्वारा चिह्नित किया गया था। हमारी नीतियों के परिणामस्वरूप 16 वर्ष में सबसे कम उधार का भारत औसत लागत और रिकॉर्ड पर सार्वजनिक ऋण के स्टॉक की उच्चतम भारत औसत परिपक्वता हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान राज्य सरकारों के लिए 6.88 प्रतिशत एवज में अतिरिक्त उधार के बावजूद केंद्र के लिए भारत उधार की लागत

1 दिसंबर को 5.82 प्रतिशत के नए स्तर पर है। सरकारी उधार कार्यक्रम - केंद्र और राज्यों दोनों - ने वर्ष में अब तक सुचारू रूप से प्रगति की है और मैंने अक्टूबर में जो कुछ भी कहा था उसे पुनः दोहराना चाहूंगा - क्रमबद्ध बाजार गतिविधियों के लिए सहकारी समाधानों का महत्वा हमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए न कि जुझारू।

वित्तीय बाजार संभावनाएं

रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम में ब्याज दरों की संरचना, जोखिम स्प्रेड की संकीर्णता और कॉरपोरेट बॉन्डों के रिकॉर्ड निर्गम करने में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। समकालीन परिपक्वता वाले जी-सेक प्रतिफल की तुलना में एएए रेटेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल 8 अक्टूबर को 60 बीपीएस से गिरकर 27 नवंबर 2020 को 17 बीपीएस हो गई। लोअर रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड पर स्प्रेड भी इसी अवधि के दौरान काफी कम था: एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड्स और बीबीबी- (बीबीबी माइनस) रेटेड 3 वर्षीय बॉन्ड्स दोनों के लिए 34 बीपीएस तक। एएए रेटेड 5-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के प्रतिफल 8 अक्टूबर 2020 को 5.93 प्रतिशत घटकर 27 नवंबर 2020 को 5.93 प्रतिशत हो गई। वास्तव में, कॉरपोरेट बॉन्ड का स्प्रेड मियादी संरचना में पूर्व-महामारी के स्तर तक सीमित है। वित्तीय बाजार एक क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। वित्त पोषण की स्थिति में ढील वास्तव में, 2020-21 की दूसरी छमाही में दिखाई देने वाली रिकवरी के नवीन संकेतों को मजबूत करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है।

ये घटनाक्रम रिज़र्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन की प्रभावकारिता से संबंधित हैं, न केवल प्रतिफल और उधार लेने की लागत को कम करने में बल्कि सकारात्मक बाजार मनोभाव के निर्माण के साथ-साथ अक्टूबर में आरबीआई द्वारा दिए गए आश्वासनों में विश्वास और इसके मार्गदर्शन में कार्रवाई करने के लिए भी। सम्पूर्ण बांड बाजार की स्थिति एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुई है और वित्तीय बाजारों के अन्य खंडों के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करता है जो जी-सेक प्रतिफल वक्र से वित्तीय लिखतों की कीमत लगाती हैं। ऋण प्रबंधन संचालन, मौद्रिक संचालन और बाजार की उम्मीदें सामंजस्य में हैं और एक समान संभावनाएं साझा करते हैं। यह वित्तीय स्थिरता के लिए शुभ संकेत है। मैं इस अवसर पर जिम्मेदार व्यवहार के लिए और

इन सकारात्मक परिणामों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बाजार सहभागियों की सराहना करना चाहता हूँ। रिज़र्व बैंक, अपनी ओर से, बाजार के प्रतिभागियों को चलनिधि और आसान वित्तपोषण स्थितियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है।

बाहरी मोर्चे में, यूएस में प्रतिफल का दृढीकरण 'रिफ्लेक्शन ट्रेड' से वृद्धि को दर्शाता है। राजनीतिक स्थिरता की संभावनाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन की उम्मीदों ने जोखिम की भूख को बढ़ा दिया है, जिससे निवेशक अमेरिकी खजाने की सुरक्षित-स्थान (सेफ हेवेन) से बाहर निकल रहे हैं और रिटर्न की तलाश कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, भारत में पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है। रिज़र्व बैंक अंतर्निहित घरेलू बुनियादों के साथ अस्थिरता को कम करने और विनिमय दर के क्रमिक विकास को सक्षम करने के लिए उपाय कर रहा है। घरेलू तरलता और मुद्रास्फीति के लिए इन कार्यों के परिणामों के प्रति जागरूक रहते हुए, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों के माध्यम से चलनिधि की उपलब्धता को प्रतिवर्ती रेपो के माध्यम से अवशोषित करके निष्फल किया जा रहा है।

हम अपने चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के साथ घरेलू स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक स्पिलओवर पर अपनी प्रतिक्रिया जारी रखेंगे। हमारे आदेश पर विभिन्न लिखतों का उपयोग उचित समय पर किया जाएगा, ताकि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सके कि सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध है। ओएमओ खरीद, परिचालन ट्विस्ट और प्रतिवर्ती रेपो जैसे लिखतों का उपयोग जारी रहेगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए और संरक्षित रखा जाए हमारा सर्वोपरि उद्देश्य संवृद्धि का समर्थन करना है।

मुद्रास्फीति और संवृद्धि का आकलन: संभावनाएं

अब मैं अंतर्निहित मुद्रास्फीति की गतिशीलता और संभावनाओं के एमपीसी के मूल्यांकन को निर्धारित करता हूँ। सीपीआई मुद्रास्फीति कुछ सबूतों के साथ कि मूल्य दबाव फैल रहा है, सितंबर में तेजी से 7.3 प्रतिशत और अक्टूबर 2020 में 7.6 प्रतिशत तक बढ़ गई। मुद्रास्फीति की संभावनाएं पिछले दो महीनों में उम्मीदों के विपरीत हो गया है। बम्पर खरीफ की फसल

की आगमन के साथ अनाज की कीमतें सौम्य हो सकती हैं और सर्दियों की फसल के साथ सब्जियों की कीमतें कम हो सकती हैं, अन्य खाद्य कीमतों में तेजी के स्तर पर बने रहने की संभावना है। लागतजन्य दबाव का कोर मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालना जारी है, जो अस्थिर रह सकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए 6.8 प्रतिशत, 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए 5.8 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही में 5.2 से 4.6 प्रतिशत तक होने की संभावना है।

बहाली और उसके बाद

इस पृष्ठभूमि पर, हमें नियंत्रित मांग को पूरा करने के बाद बहाली पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक मजबूत पथ पर स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध डाटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितना उम्मीद किया था उससे ज्यादा तेजी से सुधार हो रहा है और अक्टूबर में अपने बयान में मैंने जिस मल्टी-स्पीड सुधार को उजागर किया था उससे अधिक क्षेत्र जुड़ रहे हैं। एनएसओ के नवंबर के अंत में प्रारंभिक अनुमानों में, दूसरी तिमाही में संकुचन, अक्टूबर में लगाए गए अनुमान से अधिक हो गया है।

नवंबर 2020 में क्रमशः 56.3 और 53.7 पर विनिर्माण और सेवा क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। सेवाओं के उच्च आवृत्ति संकेतक ने बहुत से अपटिक्स (अनुलग्नक) में स्थिरता और वृद्धि दिखाई है। ग्रामीण मांग में सुधार के और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग भी गति प्राप्त कर रही है, क्योंकि अनलॉकिंग के कारण गतिविधियां और रोजगार बढ़ रहे हैं, विशेषकर कोविड-19 से विस्थापित श्रमिकों के लिए। हालांकि, ये सकारात्मक आवेग देश के कुछ इलाकों में संक्रमण के बढ़ने के संभावना के कारण धूमिल बने हुए हैं, जिससे कुछ स्थानीय रोकथाम के उपाय हो रहे हैं। इसी समय, टीके परीक्षणों में सफलताओं पर काफी आशावाद के साथ बहाली दर 94 प्रतिशत को पार कर गई है और बढ़ रही है। आने वाले वर्ष में उपभोक्ता का विश्वास आशावादी हो गया है।

2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए कॉर्पोरेट परिणाम संकेत देते हैं कि मांग की स्थिति में सुधार हो रहा है और व्यय संबंधी लागत बचत के पृष्ठभूमि में लाभ मार्जिन बढ़ रहा है और ऋण सेवा क्षमता बढ़ गई है। पिछली दो तिमाहियों में संकुचन में बने रहने के बाद निर्माण फर्मों के कारोबारी मूल्यांकन ने 2020-21 की तीसरी तिमाही में विस्तार क्षेत्र में प्रवेश किया है। 2020-21 की चौथी तिमाही में आगे बढ़ने की कारोबारी उम्मीदें बढ़ रही हैं।

संवृद्धि की संभावनाओं की ओर मुड़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ग्रामीण मांग में बहाली और मजबूत होने की उम्मीद है, जबकि शहरी मांग की गति में भी वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताएं, संभावनाओं के बारे में आशावादी बने हुए हैं और विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी मनोभाव में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। राजकोषीय प्रोत्साहन विकास-वृद्धि निवेश का समर्थन करने के लिए खपत और चलनिधि के समर्थन से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर, निजी निवेश अभी भी सुस्त है और क्षमता उपयोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जबकि निर्यात एक असमान बहाली पर है, वेक्सन पर प्रगति ने संभावनाओं को उज्ज्वल किया है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम को व्यापक रूप से संतुलित करने के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि 2020-21 में (-) 7.5 प्रतिशत, 2020-21 की तीसरी तिमाही में (+) 0.1 प्रतिशत तथा 2020-21 की चौथी तिमाही में (+) 0.7 प्रतिशत और 2021-22 की पहली छमाही में 6.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

अतिरिक्त उपाय

इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक अपने कुछ अतिरिक्त उपायों के साथ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के अपने सर्वोपरि उद्देश्य के साथ दृढ़ रहेगा ताकि (i) अन्य क्षेत्रों से संबद्ध रहने वाले लक्षित क्षेत्रों में तरलता समर्थन को बढ़ाया जा सके ; (ii) वित्तीय बाजारों को गहन किया जा सके ; (iii) विनियामक पहलों के माध्यम से बैंकों और एनबीएफसी के बीच पूंजी का संरक्षण; (iv) लेखापरीक्षा कार्यों को मजबूत करने के माध्यम से पर्यवेक्षण को मजबूत करना; (v) निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करके बाहरी व्यापार की सुविधा; तथा (vi) वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए भुगतान प्रणाली सेवाओं का उन्नयन किया जा सके।

(i) चलनिधि गतिविधि को पुनर्जीवित करने के उपाय

ऑन टैप टीएलटीआरओ- ईसीएलजीएस 2.0 के साथ क्षेत्रों और सिनर्जी का विस्तार

9 अक्टूबर 2020 को घोषित ऑन टैप लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन का विस्तार सरकार के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस 2.0) के तहत उपलब्ध क्रेडिट गारंटी के साथ अन्य तनावग्रस्त क्षेत्रों को कवर करने के लिए किया जाएगा। इससे बैंकों को कम लागत पर तनावग्रस्त क्षेत्रों में ऋण सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

(ii) वित्तीय बाजार को गहरा करना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को वर्तमान में रिजर्व बैंक की तरलता खिड़कियों के साथ-साथ कॉल / नोटिस मनी मार्केट तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। मुद्रा बाजारों में भागीदारी का विस्तार करने और बेहतर तरलता प्रबंधन की सुविधा के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक की तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; और कॉल / नोटिस मनी मार्केट भी।

भारत में अविकसित ऋण व्युत्पन्न बाजार को भरने के लिए वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए हाल ही में अधिनियमित कानून के साथ, यह निर्णय लिया गया है कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए और सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही ड्राफ्ट निदेश जारी किए जाएं। संशोधित निदेशों से ऋण व्युत्पन्न बाजार के विकास और विशेषकर कम अंकित जारीकर्ताओं के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक तरल और जीवंत बाजार की सुविधा की उम्मीद है।

वित्तीय बाजारों में विकास के उपलक्ष्य में और हाल के दिनों में किए गए विभिन्न उदारीकरण उपायों के कारण, 2011 में जारी किए गए व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पर व्यापक दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है और आज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट निदेश जारी किए जा रहे हैं। संशोधित दिशा-निर्देश बाजार के निर्माताओं द्वारा ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न व्यवसाय में शासन के उच्च मानकों और आचरण को सुनिश्चित

करते हुए व्युत्पन्न बाजारों तक कुशल पहुंच को बढ़ावा देने का एक प्रयास होगा।

कॉल, नोटिस और मियादी मुद्रा बाजार पर व्यापक ड्राफ्ट निदेशों, जमा प्रमाण पत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ आज सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किए जा रहे हैं। संशोधित निदेशों से जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों के संदर्भ में उत्पादों में निरंतरता लाने की उम्मीद है।

(iii) विनियमन

(ए) बैंक

COVID-19 महामारी के जवाब में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, उधारकर्ताओं के बीच तनाव के समाधान और अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस प्रयास की निरंतरता में और बैंकों को पूंजी संरक्षण में मदद करने के लिए, ताजा ऋण देने के उपाय करते हुए, समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंक लाभ को बनाए रखेंगे और वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबन्धित लाभ से किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे।

गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

वित्तीय प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के साथ एनबीएफसी और उनके परस्पर संबंधों के बढ़ते महत्व ने इस क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ाना अनिवार्य बना दिया है। अतः, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए मापदंडों के एक मैट्रिक्स के अनुसार पारदर्शी मापदंड रखने का निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रस्तावित मानदंडों और मापदंडों वाले एक ड्राफ्ट परिपत्र जल्द ही जारी किया जाएगा।

इसके अलावा, आनुपातिकता के सिद्धांत पर निर्मित एनबीएफसी क्षेत्र के लिए वर्तमान नियामक शासन की समीक्षा करना आवश्यक है। यह महसूस किया गया है कि एनबीएफसी के प्रणालीगत जोखिम योगदान से जुड़ा एक पैमाना-आधारित नियामक दृष्टिकोण आगे हो सकता है। हितधारक परामर्श प्रक्रिया

के हिस्से के रूप में, इस विषय पर एक चर्चा पत्र 15 जनवरी 2021 से पहले सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

(iv) पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में शासन और आश्वासन कार्यों को सुधारने में पर्यवेक्षी ध्यान रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा है। इस प्रयास में, निम्नलिखित उपायों की घोषणा आज की जा रही है। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं (i) बड़े यूसीबी और एनबीएफसी में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) की शुरुआत और (ii) वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए वाणिज्यिक बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देशों का सामंजस्य। इन उपायों पर ब्योरा विवरण के भाग-बी में हैं और उपरोक्त पर दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

(v) डिजिटल भुगतान सुरक्षा

उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सुरक्षा और सुविधा के साथ डिजिटल भुगतान चैनलों के एको सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए, हम विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण) निदेश जारी करने का प्रस्ताव रखते हैं। इन निदेशों में सुदृढ़ शासन के लिए आवश्यकताएं, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान, आदि जैसे चैनलों के लिए सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों पर कुछ न्यूनतम मानकों के कार्यान्वयन और निगरानी निहित होंगे। इस संबंध में ड्राफ्ट निदेश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

(vi) वित्तीय साक्षरता और शिक्षा

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को गहन बनाने और ग्राहकों की रक्षा के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) के माध्यम से एक समुदाय के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का कार्यान्वयन किया गया। अब मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देश के हर ब्लॉक में वर्तमान में 100 ब्लॉक से सीएफएल की पहुंच का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(vii) बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से, एक व्यापक रूपरेखा शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) ग्राहकों की शिकायतों पर खुलासे को बढ़ाना (ii) शिकायतों के निवारण की लागत की वसूली के रूप में मौद्रिक विघटन, और (iii) शिकायत निवारण तंत्रों की गहन समीक्षा करना और उनके निवारण तंत्रों में सुधार करने में विफल संस्थाओं के खिलाफ पर्यवेक्षी कार्रवाई शामिल है।

(viii) बाहरी व्यापार सुविधा

रिज़र्व बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन प्रयासों के साथ, यह निर्णय किया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी(एडी) बैंकों को अतिरिक्त शक्तियां सौंपकर बाहरी व्यापार को और अधिक सुगम बनाना है ताकि (ए) निर्यात शिपमेंट के मूल्य के बावजूद निर्यातक द्वारा शिपिंग दस्तावेजों के प्रत्यक्ष प्रेषण के मामलों को नियमित करना; (बी) निर्दिष्ट परिस्थितियों में सीमा के बिना अवास्तविक निर्यात बिल राइट-ऑफ करना; (सी) विदेशी समूह / सहयोगी कंपनियों के साथ आयात भुगतान के लिए निर्यात प्राप्ति के सेट-ऑफ करने की अनुमति कुछ शर्तों के तहत दी जाएगी जब निर्यात और आयात दोनों एक ही कैलेंडर वर्ष के भीतर हुए हों; तथा (डी) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन, आयात करने वाले देश में माल के आयात पर जोर दिए बिना, जो प्रकृति में खराब हो रहे हैं या बंदरगाह / सीमा शुल्क / स्वास्थ्य अधिकारियों / किसी अन्य मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा नीलाम / नष्ट कर दिए गए हैं, के बिना निर्यात आय के रीफंड पर विचार किया जा सके।

(ix) भुगतान और निपटान प्रणाली

जल्द ही आरटीजीएस प्रणाली 24x7 कर दी जाएगी। इस सक्षमता के साथ, सिस्टम में निपटान और डिफॉल्ट जोखिम को कम करने का प्रस्ताव है, जो सप्ताह के सभी दिनों में एईपीएस, आईएमपीएस, एनईटीसी, एनएफएस, रुपये, यूपीआई लेनदेन के

निपटान की सुविधा प्रदान करता है। इससे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र अधिक कुशल हो जाएगा।

सावधानी और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान को अपनाने का विस्तार करने के लिए, उपयोगकर्ता के विवेक पर, कार्ड के माध्यम से आवर्ती लेनदेन (और UPI) के लिए संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और ई-जनादेश की सीमा 1 जनवरी 2021 से ₹2,000 to ₹5,000 को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

निष्कर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए वृद्धि में तेजी आई है। सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत उपायों का उद्देश्य इन वृद्धि को अधिक मजबूती के लिए पोषण करना है। वायरस के बारे में संज्ञान और सावधानी के साथ, अर्थव्यवस्था के एक अंशकालिक अनलॉकिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। सतर्क रहते हुए, हमें अब महामारी द्वारा छोड़े गए निशान को कम करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की ओर मुड़ना चाहिए। वेक्सिन पर सकारात्मक समाचारों की स्थिति और स्वस्थ होने में लगातार वृद्धि के साथ क्षितिज और भी प्रकाशमान हो गया है। भारत का समय COVID-19 के भ्रूण से मुक्त होने और हमारे भाग्य को फिर से समनुरूप बनाने का आ गया है। हम दृढ़ता और साहस के साथ पैदा हुए हैं, जो महामारी के कहर का सामना कर सकते हैं। हमने जीवन और प्रियजनों को खो दिया है, लेकिन आशा नहीं, और दृढ़ विश्वास नहीं कि हम इस पर विजयी होंगे और मजबूत बनेंगे। यह अक्सर कहा जाता है कि COVID के बाद का जीवन फिर से पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन समय ने मानव प्रयास से दिखाया गया है कि एक नई दुनिया की तलाश में कभी देर नहीं होती है। हमें प्रयास करने, खोजने और नहीं हारने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ बढ़ना चाहिए। मुझे सुकरात द्वारा उद्धृत एक उद्धरण यहाँ याद आ रहा है, "विपत्ति के सामने, हमारे पास एक विकल्प है। हम कड़वे हो सकते हैं, या हम बेहतर हो सकते हैं"। जाहिर है हम बेहतर होने का प्रयास करेंगे।

सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

संलग्नक: उच्च आवृत्ति संकेतक- दिसंबर 03, 2020 की स्थिति (जारी)

फरवरी 2020 = 100

क्रम सं.	संकेतक	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं
1	कृषि / ग्रामीण माँग										
	ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री*	100	41	15	76	89	101	119	98	84	
	दोपहिया की बिक्री*	100	69	0	20	72	89	100	108	123	
	तिपहिया की बिक्री*	100	64	0	7	29	34	34	38	50	
	कृषि निर्यात*	100	79	64	88	95	109	101	114	116	
	उर्वरक बिक्री*	100	80	135	105	93	107	96	94	115	
	कृषि ऋण (बकाया)	100	100	100	99	100	101	101	103	105	
	मनरेगा कार्य की माँग (हाउसहोल्ड्स)	100	93	60	168	201	144	109	109	109	100
2	औद्योगिक उत्पादन										
	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक*	100	79	45	67	80	89	88	92		
	आईआईपी: विनिर्माण*	100	77	35	63	80	89	88	92		
	आईआईपी: पूँजीगत वस्तुएँ*	100	68	9	40	69	80	83	92		
	आईआईपी: इंफास्ट्रक्चर एवं निर्माण वस्तुएँ*	100	75	17	61	78	90	90	92		
	आईआईपी: टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ*	100	66	5	33	67	81	87	96		
	आईआईपी: गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ*	100	78	53	91	115	103	98	102		
	आठ प्रमुख उद्योग (ईसीआई) सूचकांक*	100	88	62	76	83	89	87	89	88	
	ईसीआई : स्टील*	100	79	21	62	79	94	94	94	92	
	ईसीआई : सीमेंट*	100	73	16	71	82	79	74	83	86	
	इलेक्ट्रीसिटी माँग	100	95	82	99	101	108	105	108	106	94
	ऑटोमोबाइल्स उत्पादन										
	यात्री वाहन*	100	67	0	11	44	70	83	102	114	
	दोपहिया*	100	77	0	17	58	81	99	112	129	
	तिपहिया*	100	69	0	37	43	41	56	59	71	
	ट्रैक्टरों का उत्पादन*	100	52	0	37	101	90	95	102	114	
3	निर्माण										
	स्टील उपभोग*	100	80	19	61	80	103	96	100	106	
	सीमेंट उत्पादन*	100	73	16	71	82	79	74	83	86	
4	यातायात										
	ऑटोमोबाइल्स की बिक्री*	100	65	0	19	67	83	94	103	116	
	यात्री वाहनों की बिक्री*	100	53	0	14	51	74	87	101	111	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	100	60	0	3	17	17	24	33	38	
	घरेलू हवाई कार्गो*	100	66	8	17	50	57	63	76	82	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो*	100	70	25	42	62	70	72	81	81	
	मालभाड़ा निवल टन किलोमीटर*	100	84	65	76	87	90	93	100	101	102
	पोर्ट कार्गो*	100	92	78	73	84	86	88	94	92	
	कर संग्रह : मात्रा	100	77	9	50	74	79	88	100	111	113
	पेट्रोलियम उपभोग*	100	81	50	77	86	85	78	89	93	
5	घरेलू व्यापार										
	जीएसटी ई-वे बिल	100	71	15	45	76	85	86	100	112	97
	जीएसटी राजस्व	100	93	31	59	86	83	82	91	100	100

संलग्नक: उच्च आवृत्ति संकेतक- दिसंबर 03, 2020 की स्थिति (समाप्त)											
क्रम सं.	संकेतक	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून	जुला	अग	सितं	अक्टू	नवं
6	पर्यटन एवं आतिथ्य										
	विदेशी पर्यटक आगमन	100	32	0	0	0	0	0	0		
7	बाह्य व्यापार										
	पण्य निर्यात	100	77	37	69	79	85	82	99	89	84
	पण्य आयात	100	83	46	59	56	76	79	80	89	88
	गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात	100	82	50	75	63	81	78	96	103	101
	सेवाओं का निर्यात	100	102	93	95	96	96	93	98		
	सेवाओं का आयात	100	100	84	90	90	91	87	92		
8	भुगतान और निपटान संकेतक (मात्रा)										
	आरटीजीएस	100	89	41	68	90	94	88	98	104	99
9	मौद्रिक, बैंकिंग और वित्तीय समुच्चय										
	बकाया ऋण	100	103	102	101	102	102	101	102	102	103
	बैंक जमा	100	102	103	105	104	106	106	107	107	108
	जीवन बीमा पहले वर्ष का प्रीमियम	100	137	36	74	156	124	146	137	123	
	गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	100	113	0	0	100	122	126	165	114	
	एम3	100	102	103	105	105	107	107	108	108	109
	आरक्षित मुद्रा	100	102	102	105	107	107	107	107	109	111
	सीपी: मासिक बकाया	100	86	104	106	98	94	93	91	95	
	सीडी: मासिक बकाया	100	93	97	86	65	56	49	41	42	
	एफपीआई निवल (मिलियन यूएस डालर)	1271	-15924	-1961	-973	3441	451	6662	-157	2974	8458
	एमएफ निवेश- इक्विटी (आईएनआर करोड़)	9863	30131	-7966	6523	-502	-9195	-8400	-4134	-14492	-22665
	एमएफ निवेश- कर्ज (आईएनआर करोड़)	18026	-16190	-9795	10699	41365	31898	24494	17005	30996	13129
	कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम (आईएनआर करोड़)	80555	75734	54741	84871	70536	48122	58419	64389	62631	
10	पीएमआई										
	पीएमआई: विनिर्माण (>50 पिछले माह की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है)	54.5	51.8	27.4	30.8	47.2	46	52	56.8	58.9	56.3
	पीएमआई: सेवाएं (>50 पिछले माह की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है)	57.5	49.3	5.4	12.6	33.7	34.2	41.8	49.8	54.1	53.7
	पीएमआई: संयुक्त (>50 पिछले माह से वृद्धि को दर्शाता है)	57.6	50.6	7.2	14.8	37.8	37.2	46	54.6	58.0	56.3
11	रोजगार										
	सीएमआईई बेरोजगारी दर (%)	7.8	8.8	23.5	21.7	10.2	7.4	8.4	6.7	7.0	6.5

*मौसमी आधार पर समायोजित आंकड़ों को दर्शाता है

स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी, एनएसओ, मांस्पी, आरबीआई, सेबी, एफआईएमएमडीए

← कोविड-पूर्व स्तर से नीचे		गतिविधि में बहाली आना/सामान्य होना →		